

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था प्रस्तावित है। विस्तृत दिशा निर्देश यथा दायित्व एवं कर्तव्य बेवसाईट पर उपलब्ध है।

सहायता सौंधी राजमुच्य ग्रामीण रोजगार ग्युटो अधिनियम की धारा- 27(1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के निम्नलिखित जिलों यथा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जमुई, मधुबनी, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी, अररिया, अरवल, बांका, पूर्वी चम्पारण, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, सिवान, सुपौल एवं सहरसा जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के बेवसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 30.05.2015, 17.00 बजे तक होगी।

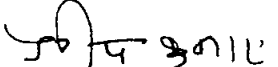
नियुक्ति के शर्तें :-

लोकपाल Ombudsman के पद पर 2 वर्षों के लिए होगा। उसके पद पर प्रकटित कार्य के समीक्षोपरान्त उन्हें अधिकतम 2 बार एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

- लोकपाल (Ombudsman) के प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 20,000/- रूपये प्रति माह देय होगा। इसके अलावे किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। जाँच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी।
- लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा।
- आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों।

योग्यता:- अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो तथा लोक प्रशासन यथा अपर समाहर्ता एवं उच्च स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, विधि यथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च स्तर के सेवानिवृत्त विधि पदाधिकारी, अभियंत्रण सेवा यथा अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के सेवा निवृत्त अभियंता, सामाजिक कार्य में संबद्ध व्यक्ति जो 20 वर्षों से अन्यून ख्याति प्राप्त NGO के कार्य अनुभव रखते हों।

उम्र सीमा:- अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 31.01.2016 के आधार पर)।


सचिव, 20.5.15

ग्रामीण विकास विभाग।


20/5/15